



Neutral Citation No. - 2026:AHC:71072-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 209/2026

वीरेश चन्द्र मिश्रा एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रशांत शुक्ला, राम प्रकाश उपाध्याय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

एवं 4 अन्य वाद सम्बद्ध।

प्रतिवेद्य

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

(विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 174/2026 में दायर सिविल प्रकीर्ण अपील पर अनुमति प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 एवं सिविल प्रकीर्ण छूट प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 पर आदेश)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. किसी भी गंभीर आपत्ति के अभाव में, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(विशेष अपील पर आदेश)

3. मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला, अपर महाधिवक्ता श्री कार्तिकेय सरन और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अंकित गौड़ को सुना।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वर्तमान अंतर-न्यायालय अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश के सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 27.01.2026, समित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य और 11 संबंधित रिट याचिकाएं, 2026:एचसी:17253 के खिलाफ उत्पन्न हुई हैं। उस आदेश द्वारा, रिट न्यायालय ने मूल याचिकाकर्तागण-अपीलकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। वास्तव में, रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें प्रत्यर्थी राज्य प्राधिकरणों को राज्य सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत कवर किए गए विभिन्न इंटर-कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को देय वेतन के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

5. मुख्य रूप से, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023, (इसके बाद 'आयोग अधिनियम' के रूप में संदर्भित), और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियम, 2023 (इसके बाद 'आयोग नियम' के रूप में संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए, मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के बराबर वेतन प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है, हालांकि यह पक्षकारण के बीच एक स्वीकृत प्रकरण है कि मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे अपने-अपने इंटरमीडिएट कॉलेजों में- सभी राज्य सरकार की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऐसा करते हुए रिट न्यायालय ने कहा है कि धनेश्वर सिंह चौहान बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, 1980 0 यूपीएलबीईसी 286, नरबेश्वर मिश्रा बनाम विद्यालय जिला निरीक्षक, देवरिया, 1982 0 यूपीएलबीईसी 171 और सोलोमन मोरार झा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया और अन्य, 1985 यूपीएलबीईसी 113 में समन्वय पीठों के पहले के तीन निर्णय अब अच्छे कानून नहीं हैं।

6. तैयार संदर्भ के लिए, रिट-ए संख्या 19255, वीरेश चंद्र मिश्रा और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। मूल याचिकाकर्ता, वीरेश चंद्र मिश्रा को शुरू में 16.08.2001 को सेवा चयन बोर्ड द्वारा व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 16.10.2001 के आदेश के तहत स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज, सुरजावली वाया खुर्जा, बुलंदशहर आवंटित किया गया था। दिनांक 18-10-2001 के नियुक्ति पत्र के विरुद्ध वह उस संस्था में शामिल हो गया। 30.12.2022 को उक्त संस्था के तत्कालीन प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने याचिकाकर्ता को प्रभार सौंप दिया, जो संस्थान में काम करने वाले सबसे वरिष्ठ व्याख्याता थे।



7. इसके बाद, 13.1.2023 को डी.आई.ओ.एस., बुलंदशहर द्वारा याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर को सत्यापित किया गया। तब से, याचिकाकर्ता उस संस्था के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है और वह उस क्षमता में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। हालांकि, उन्हें प्रधानाचार्य के पद के अनुरूप वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिस पर उन्होंने कार्य किया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की। इसका निस्तारण कर दिया गया है।

8. कुछ अन्य याचिकाओं में, तथ्यों में थोड़ा अंतर मौजूद है, क्योंकि कुछ याचिकाकर्तागण को उनके संबंधित संस्थानों के प्रमुख के रूप में उनके कार्यवाहक वेतन के अनुरूप वेतन का भुगतान किया जा रहा था। आयोग अधिनियम के लागू होने पर, उस वेतन भुगतान को रोक दिया गया है।

9. हमने पक्षकारगण के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है। याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुतियां सबसे पहले मूल याचिकाकर्ता वीरेश चंद्र मिश्रा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत शुक्ला द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। वह प्रस्तुत करेगा- प्रारंभ में, उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'इंटरमीडिएट एक्ट' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के तहत, और उसके तहत बनाए गए विनियमों, प्रधानाचार्य के पद पर अस्थायी या मूल रिक्ति पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए प्रावधान मौजूद था। उस समय, एक विवाद उत्पन्न हुआ, यदि एक इंटरमीडिएट कॉलेज का एक कार्यवाहक प्राचार्य प्रधानाचार्य के बराबर वेतन का भुगतान करने का हकदार था। **धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त)** में, याचिकाकर्ता ऐसे संस्थान में स्थायी व्याख्याता था। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के काम के विरुद्ध प्रधानाचार्य के वेतन के भुगतान के दावे की अनुमति देते हुए, एक समन्वय पीठ ने माना था कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक का वेतन मध्यवर्ती अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा, इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय III के तहत विनियम 46 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप होगा। दिनांक 18.01.1974 के एक शासकीय आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित करने वाली उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, उक्त शासकीय आदेश के खंड 5(2) को एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य या कार्यवाहक शिक्षक को उच्च ग्रेड में वेतन देने का अधिकार देने के लिए पढ़ा गया था, जो उस पद के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुरूप है जिस पर ऐसे व्यक्ति ने कार्य किया हो। राज्य सरकार की ओर से यह स्थापित करने में विफलता के लिए कि कोई बाद का शासकीय आदेश जारी किया गया था या कोई अन्य नियम लागू किया गया था, एक अन्य योजना का प्रावधान करते हुए और आगे यह स्थापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कि दावेदार याचिकाकर्ता दावा किए गए उच्च वेतन का हकदार नहीं था, डीआईओ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और एक सकारात्मक निर्देश जारी किया गया, उच्च वेतन के भुगतान के लिए।

10. फिर **नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त)** का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि उस प्रकरण में, **धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त)** में अनुपात लागू किया गया था और उसका पालन किया गया था। विशेष रूप से पहले अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमन 2 के खंड 3 का उल्लेख करते हुए, **नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त)** में एक समन्वय पीठ ने आगे कहा कि उच्च वेतन का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक जारी रहने पर होगा। इसके बाद, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दावेदार याचिकाकर्ता ने छह महीने की अवधि से अधिक समय तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य की क्षमता में काम करना जारी रखा था, उसे उच्च वेतन के भुगतान का हकदार पाया गया।

11. न केवल 40 साल से अधिक समय पहले **धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त)** और **नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त)** में समन्वय पीठों की घोषणाओं के माध्यम से यह सुसंगत दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ था, बल्कि **सोलोमन मोरार झा (पूर्वोक्त)** में, उक्त सिद्धांत को अल्पसंख्यक संस्थानों तक भी विस्तारित किया गया था। हाल ही में, एक अन्य समन्वय पीठ ने वर्तमान विधायी संदर्भ में अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी यही सिद्धांत लागू किया है। इस प्रकार, **उत्तर प्रदेश राज्य और दो अन्य बनाम सखावत उल्लाह खान और अन्य, 2026:एचसी:25538:डीबी** में, **सोलोमन मोरार झा (पूर्वोक्त)** में निर्णय के बाद एक पीठ द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें से हम में से एक घटक था।

12. जहां तक सांविधिक प्रावधान का सवाल है, श्री शुक्ला ने सबसे पहले उसके तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय 2, विनियम 2 का उल्लेख किया है। इस प्रकार, उस विनियम के खंड 2 के उप-खंड (1) के परंतुक पर भरोसा किया गया है। तैयार संदर्भ के लिए, इसे नीचे दिया गया है: -

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



"2 (1) संस्था के प्रमुख का पद खंड (2) में प्रदान किए गए के रूप में के रूप में के रूप में प्रदान किए को छोड़कर धारा 16-एफ की उप-धारा (1) के तहत गठित चयन समिति के संदर्भ के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा या, जैसा भी प्रकरण हो, धारा 16-एफएफ की उप-धारा (1) के तहत:

बशर्ते कि किसी संस्था के धारा 16-एफएफ में निर्दिष्ट संस्था नहीं होने की स्थिति में किसी पदधारी को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण होने वाली अस्थायी रिक्ति या संस्थाप्रमुख के पद पर शैक्षिक सत्र के दौरान होने वाली किसी अवलंबी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या निलंबन से वरिष्ठ योग्य शिक्षक की पदोन्नति से भरी जाएगी, यदि कोई हो, तो संस्थान में उच्चतम ग्रेड में।

3) जहां संस्था के प्रमुख के पद में अस्थायी रिक्ति है, वहां तीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए उच्चतम ग्रेड में वरिष्ठतम शिक्षक को संस्था के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह उस वेतनमान से अधिक पैमाने पर भुगतान करने का हकदार नहीं होगा जिसमें वह ऐसे शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है।

प्रभाव वर्द्धित

उस विधायी योजना की व्याख्या धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त) और नरबेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा की गई थी।

13. उक्त निर्णय के बाद, विधायी कार्यवाई का पालन किया गया। धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त) और नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त) में अनुपात को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (इसके बाद 'बोर्ड अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को शामिल करने पर विधायी अभिव्यक्ति मिली। उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत, सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रूप में तदर्थ पदोन्नति के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था। तैयार संदर्भ के लिए बोर्ड अधिनियम की धारा 18 नीचे दी गई है: -

"धारा 18: तदर्थ प्रधानाचार्य या हेडमास्टर

(1) जहां प्रबंधन ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार बोर्ड को रिक्ति अधिसूचित की है और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का पद वास्तव में दो महीने से अधिक समय तक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिक्त रहा है, वहां प्रबंधन वरिष्ठतम शिक्षक को पदोन्नत करके विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर ऐसी रिक्ति को भरेगा।

(क) प्रधानाचार्य के पद में रिक्ति के संबंध में व्याख्याता के ग्रेड में।

(ख) प्रधानाध्यापक के पद में रिक्ति के संबंध में प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में।

(2) जहां प्रबंधन उपधारा (1) के अधीन वरिष्ठतम शिक्षक को पदोन्नत करने में विफल रहता है, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे शिक्षक की पदोन्नति का आदेश जारी करेगा और संबंधित शिक्षक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा भी प्रकरण हो, उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नति के ऐसे आदेश का अनुसरण करता है।

(3) जहां वह शिक्षक जिसे उपधारा (2) के अधीन पदोन्नति का आदेश जारी किया गया है, वह प्रबंधन की ओर से किसी कार्य या चूक के कारण, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है, ऐसा शिक्षक निरीक्षक को अपनी कार्यभार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा और उसके बाद प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा भी प्रकरण हो, उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस समय से प्रभावी नहीं होगी जब बोर्ड द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी पद ग्रहण करता है।

14. वह विधायी योजना 40 से अधिक वर्षों तक लागू रही। हालांकि आयोग अधिनियम के लागू होने पर, बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही इंटरमीडिएट अधिनियम और विनियमों के तहत शासित शिक्षकों की सेवा की शर्तों को उक्त अधिनियम की धारा 16 के आधार पर बचाया गया है। आयोग अधिनियम की धारा 31 का उल्लेख करते हुए, यह आगे प्रस्तुत किया गया है, जबकि बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, इंटरमीडिएट अधिनियम लागू है। तैयार संदर्भ के लिए धारा 16 और 31 या आयोग अधिनियम नीचे पढ़ें: -



16. शिक्षकों या अनुदेशकों की सेवा की शर्तें- शिक्षक या अनुदेशक की सेवा की शर्तें संबंधित अधिनियमों/सेवा नियमों/विनियमों/विश्वविद्यालय की मूर्तियों, जैसा भी प्रकरण हो, में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तय की जा सकती हैं।

31. निरसन एवं बचत :- (1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई या की गई मानी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी भौतिक समयों पर लागू हों।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अलावा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन का उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम, 1904 (1904 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. इस प्रकार, भले ही बोर्ड अधिनियम निरस्त हो जाता है, कानून में सिद्धांत, प्रधानाचार्य के पद के अनुरूप, एक अनुदान सहायता इंटरमीडिएट कॉलेज के एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के लिए उच्च वेतन के भुगतान के लिए प्रदान करता है, जो कि मूल रिक्ति के खिलाफ उस क्षमता में कार्य कर सकता है, धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त) और नरबेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त) में समन्वय पीठों के पूर्व-मौजूदा निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से मौजूद है।

16. उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड अधिनियम के लागू होने और इसके निरसन के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। इसलिए, धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त) और नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त) से निकलने वाला न्यायिक सिद्धांत अब मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले बोर्ड अधिनियम की धारा 10 और 16 का उल्लेख किया है। वे प्रावधान नीचे दिए गए हैं: -

“10. सीधी भर्ती द्वारा चयन की प्रक्रिया- (1) किसी शिक्षक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, सीधी भर्ती द्वारा, प्रबंधन भर्ती के वर्ष के दौरान विद्यमान या रिक्त होने की संभावना वाली रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रमुख के पद के अलावा



किसी अन्य पद के प्रकरण में, अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा, (ख) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए एक समिति की स्थापना करना है और रिक्तियों को ऐसे रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से जो विहित किया जाए, बोर्ड को अधिसूचित करना है।

(2) शिक्षकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो निर्धारित की जाए:

परन्तु प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से बोर्ड उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

16. नियुक्ति केवल बोर्ड की सिफारिश पर की जाएगी- (1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके तहत बनाए गए विनियमों में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन 3 [4 के उपबंधों के अधीन] धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, [21-ई, 21-एफ, 21-जी, 33, 33-ए, 33-बी, 33-सी, 33-डी, और 33-एफ और 33-जी], उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शिक्षक की प्रत्येक नियुक्ति प्रबंधन द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जाएगी।”

17. उपरोक्त प्रावधानों को केवल नियमित नियुक्ति के प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है। उनके पास प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति के खिलाफ तदर्थ नियुक्ति और तदर्थ पदोन्नति के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के तहत किया गया था। यह इस प्रकार है:-

“18. तदर्थ प्रधानाचार्य या हेडमास्टर- (1) जहां प्रबंधन ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार बोर्ड को रिक्ति अधिसूचित की है और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का पद वास्तव में दो महीने से अधिक समय तक रिक्त रहा है, वहां प्रबंधन वरिष्ठतम शिक्षक को पदोन्नत करके विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर ऐसी रिक्ति को भरेगा।



(क) प्रधानाचार्य के पद में रिक्ति के संबंध में व्याख्याता के ग्रेड में।

(ख) प्रधानाध्यापक के पद में रिक्ति के संबंध में प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में।

(2) जहां प्रबंधन उपधारा (1) के अधीन वरिष्ठतम शिक्षक को पदोन्नत करने में विफल रहता है, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे शिक्षक के प्रस्तावना-प्रस्ताव का आदेश जारी करेगा और संबंधित शिक्षक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा भी प्रकरण हो, उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नति के ऐसे आदेश का अनुसरण है।

(3) जहां वह शिक्षक जिसे उपधारा (2) के अधीन पदोन्नति का आदेश जारी किया गया है, वह प्रबंधन की ओर से किसी कार्य या चूक के कारण, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है, ऐसा शिक्षक निरीक्षक को अपनी कार्यभार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा और उसके बाद प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा भी प्रकरण हो, उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत तदर्थ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति तब से प्रभावी नहीं होगी जब बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार पद में शामिल हो जाता है।”

18. पूर्ण प्रभाव देने के लिए, उस प्रावधान को बोर्ड अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 11 (4) के साथ पढ़ा जाना था। तैयार संदर्भ के लिए नियम 11 (4) नीचे दिया गया है:-

“11. रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना- (4) जहां भर्ती के किसी वर्ष के लिए, प्रबंधन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट तारीख तक रिक्तियों को अधिसूचित नहीं करता है या उक्त उप-नियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में विफल रहता है, वहां निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर, धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों का निर्धारण करेगा और उन्हें बोर्ड को इस रीति से और उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट तिथि। इस उप-नियम के तहत बोर्ड को अधिसूचित रिक्तियों को अधिसूचित माना जाएगा?



19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है, प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ पदोन्नति करने के प्रयोजनों के लिए, विधायी इरादा सामने आया था कि रिक्ति को पहले संस्था की प्रबंधन समिति द्वारा बोर्ड को अधिसूचित किया जाना चाहिए। केवल अगले दो महीनों के भीतर बोर्ड की ओर से महत्वपूर्ण नियुक्ति करने में विफल रहने की स्थिति में, प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करने का अवसर उत्पन्न होगा। वह योजना इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत पहले से मौजूद योजना से भौतिक रूप से अलग थी। फिर, बोर्ड अधिनियम की धारा 32 का संदर्भ दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मध्यवर्ती अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि वे बोर्ड अधिनियम के लिए असंगत नहीं हो सकते हैं, लागू किए जाते रहेंगे। उस अधिनियम के तहत, प्रधानाचार्य के पद पर कोई तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति नहीं की जा सकती है, जब तक कि प्रबंधन समिति द्वारा बोर्ड को रिक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है, इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत पहले से मौजूद योजना को स्पष्ट रूप से बदल दिया गया था और इसलिए इसे अप्रवर्तनीय बना दिया गया था। आयोग अधिनियम की बात करें तो धारा 10 के उपबंधों पर भरोसा किया गया है, जिसे बोर्ड अधिनियम के उपबंध 10 के समानांतर एक उपबंध बताया गया है। बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप किसी भी प्रावधान के अभाव में (जैसा कि प्रधानाचार्य के पद के लिए तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है), यह प्रस्तुत किया गया है कि आयोग अधिनियम तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति पर विचार नहीं करता है।

20. आयोग अधिनियम की धारा 30 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है, भले ही इंटरमीडिएट अधिनियम में दूसरों के विपरीत कुछ भी निहित हो। धारा 30 के तैयार संदर्भ प्रावधानों के लिए नीचे दिया गया है: -

“30. अधिनियम का प्राधान्य प्रभाव (Overriding Effect of the Act) –

शिक्षकों अथवा प्रशिक्षकों के चयन के संबंध में, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे, भले ही उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली, 2021 में निहित नियमों, विनियमों अथवा उपविधियों में इसके विपरीत कोई भी प्रावधान क्यों न हो?



21. इसके बाद, आयोग अधिनियम की धारा 31(3) का भी संदर्भ दिया गया है। यह इस प्रकार है:-

“31. निरसन एवं बचत - (1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई या की गई मानी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी भौतिक समयों पर लागू हों।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के अलावा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन का उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम, 1904 (1904 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के साथ, यह प्रस्तुत किया गया है कि बोर्ड अधिनियम के निरसन की तारीख को, मध्यवर्ती अधिनियम के असंगत प्रावधान को पुनर्जीवित नहीं किया गया था और इसलिए, उस अधिनियम के तहत विकसित की गई योजना जीवित नहीं है। नतीजतन, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट न्यायालय ने मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

23. स्पष्टीकरण और आपत्ति के माध्यम से, यह भी कहा गया है कि आयोग अधिनियम के प्रभाव को रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। नतीजतन, इस पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान कार्यवाही में इस मुद्दे को पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

24. रवींद्र सिंह निरंजन बनाम स्कूलों के जिला निरीक्षक, झांसी और अन्य, 1988 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4: (1988) 1 एडब्ल्यूसी 658 में एक अन्य समन्वय पीठ के निर्णय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के तहत रिक्तियों की अधिसूचना कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में उच्च वेतन का दावा करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। दूसरा, मुनीश्वर दत्त पांडे बनाम रामजीत तिवारी और अन्य (1997) 3



सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण 599 का उल्लेख करते हुए, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उचित प्रक्रिया यानी रिक्ति की अधिसूचना का पालन किए बिना की गई कोई भी नियुक्ति बोर्ड अधिनियम की धारा 18 से बाहर रहेगी।

25. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले, हम पाते हैं कि उठाया गया मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है। इसमें तथ्यों पर कोई विवाद शामिल नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान कार्यवाही अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से उत्पन्न हुई है। वे रिट याचिका की निरंतरता हैं। नतीजतन, मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण के उच्च वेतन के दावे पर तीन अधिनियमों के प्रभाव के रूप में आगे की गई कानूनी प्रस्तुतियों पर उस प्रकाश में विचार किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य की ओर से उठाई गई तकनीकी आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय के समक्ष एक विशुद्ध कानूनी मुद्दा उत्पन्न होने के बाद, हम इसे स्वयं के बल पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।

26. पहली बात तो यह है कि बोर्ड अधिनियम के प्रवर्तन तक पक्षकार विवाद में नहीं हैं। धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून अस्तित्व में था। उस समन्वय पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी: -

“याचिकाकर्ता सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षक है और उत्तर प्रदेश हाई विद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के तहत उसके वेतन के लिए दायित्व राज्य सरकार पर है। सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षक के वेतन को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम द्वारा विनियमित किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश अध्याय III में विनियम 46 में यह निर्धारित किया गया है कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1974 को उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया था। शासकीय आदेश के पैरा 5(2) में यह निर्धारित किया गया है कि एक शिक्षक उच्च ग्रेड वाले पद पर कार्य करते समय उच्च ग्रेड में वेतन देने का हकदार है और इसमें उच्च ग्रेड में कार्यवाहक शिक्षक के वेतन का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई है। याचिकाकर्ता द्वारा शासकीय आदेश की एक प्रति हमारे सामने थी। प्रत्यर्थी याचिकाकर्तागण के इस कथन से इनकार नहीं करते हैं कि राज्य सरकार ने उच्च ग्रेड में एक शिक्षक को वेतन देने के आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्तागण के दावे को प्रधानाचार्य ग्रेड में वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपरोक्त शासकीय आदेश के अनुसरण में मंजूरी दी गई थी। प्रत्यर्थी दिनांक 24-1-74 के शासकीय आदेश में निहित निर्देश का स्थान लेने वाले किसी भी बाद के शासकीय आदेश या नियम को दिखाने में विफल रहे हैं। प्रत्यर्थी न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री रखने में विफल रहे हैं जो यह दिखाते हुए कि याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते समय प्रधानाचार्य के ग्रेड में वेतन का हकदार नहीं था। इसलिए 31-8-77 के विद्यालय निरीक्षक का आदेश कानून में पोषणीय नहीं है।

“3. परिणाम में हम याचिका की अनुमति देते हैं और विद्यालय के जिला निरीक्षक के आदेश को रद्द करते हैं और प्रत्यर्थीगण को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए प्रधानाचार्य ग्रेड में वेतन का भुगतान करें, जिसके दौरान वह विद्यालय के जिला निरीक्षक के पत्र में निहित आदेशों के अनुसार प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता अपनी लागत का हकदार है।”

27. उस सिद्धांत को नरबेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त) में एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा दोहराया गया था। उसमें, यह नीचे के रूप में देखा गया था:

“7. धनेश्वर सिंह चौहान बनाम विद्यालय जिला निरीक्षक, बदायूं 1980 यूपीएलबीईसी 286 में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक 18-1-1974 के शासकीय आदेश द्वारा प्रदान किए गए प्रधानाचार्य ग्रेड में वेतन प्राप्त करने का हकदार है। यह निर्णय याचिकाकर्तागण के तर्क का समर्थन करता है।

8. यही निष्कर्ष ऊपर उद्धृत विनियमन संख्या 2 के खंड (3) से भी निकलता है। यह प्रावधान कि जहां संस्थान के प्रमुख के अतीत में अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए है, वरिष्ठतम शिक्षक को संस्थान के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह उस पैमाने से अधिक पैमाने पर भुगतान करने का हकदार नहीं होगा जिसमें वह एक शिक्षक के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहा था 80 दिनों से अधिक, पूर्वोक्त परंतुक के तहत प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त शिक्षक एक प्रधानाचार्य को स्वीकार्य वेतन का हकदार होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. इसलिए, उपरोक्त वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि याचिकाकर्ता, कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य के वेतन का भुगतान करने का हकदार था। परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के वेतन से इनकार करने का औचित्य इस आधार पर नहीं किया कि याचिकाकर्ता केवल प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा था।

10. जहां तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता के तर्क का संबंध है कि विभिन्न कठिनाइयों को हटाने के आदेशों के तहत कार्यवाहक नियुक्ति केवल छह महीने की अवधि के लिए चल सकती है, यह कहना पर्याप्त है कि, यह वह आधार नहीं था जिस पर स्कूलों के जिला निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य ग्रेड में वेतन के भुगतान से इनकार कर दिया गया था। दूसरी ओर, अनुलग्नक 4 से रिट याचिका तक, जो 3 जुलाई 1981 को शिक्षा उपनिदेशक के पत्र की एक प्रति है, जो विद्यालय के जिला निरीक्षक को संबोधित है (याचिकाकर्ता को एक प्रति अग्रोषित के साथ) यह स्पष्ट है कि 'याचिकाकर्ता को अभी भी कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में माना जा रहा था, शिक्षा उप निदेशक ने कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को वेतन के भुगतान पर लागू प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की ओर इशारा किया और कहा कि विद्यालय के जिला निरीक्षक को उन प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इसलिए, हमें विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस निवेदन में कोई दम नहीं मिलता है।

11. परिणाम में, याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्यों को स्वीकार्य वेतन का भुगतान करें, जब तक कि याचिकाकर्ता उपरोक्त कॉलेज का कार्यवाहक प्राचार्य बना रहे। हालाँकि, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।”

28. उन समन्वय पीठों द्वारा निर्धारित कानून की शुद्धता के बारे में किसी भी विवाद के अभाव में, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पहले इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत, कोई भी शिक्षक जो अनुदान सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर सकता है, उस संस्थान के प्रधानाचार्य के अनुरूप उच्च वेतन के भुगतान का हकदार हो जाएगा।

29. इसके बाद, बोर्ड अधिनियम के प्रवर्तन पर, उस कानूनी सिद्धांत को उक्त अधिनियम की धारा 18 (ऊपर निकाले गए) की धारा 18 के आकार और रूप में वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। इसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 11(4) के साथ पढ़ें, केवल एक अंतर जो



सामने आया वह नियमों के नियम 11(4) के स्वयं के बल पर था। इस प्रकार, तदर्थ प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रबंधन समिति के हाथों नियम 11(1) के अनुसार, नियम 11(2) के साथ पठित है। केवल प्रबंधन समिति की ओर से विफलता की स्थिति में, डीआईओएस स्वयं संस्थान में रिक्ति का निर्धारण करेगा।

30. उस प्रकाश में, **मुनीश्वर दत्त पांडे (पूर्वोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि बोर्ड अधिनियम की धारा 18 के तहत कोई भी नियुक्ति करने से पहले, प्रबंधन समिति को रिक्ति को अधिसूचित करना चाहिए था। हम ध्यान देते हैं कि उक्त निर्णय में, मुद्दा पूरी तरह से अलग था। वहां, निवर्तमान प्रधानाचार्य ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को पूर्व सूचना के साथ संस्थान के वरिष्ठतम व्याख्याता को प्रभार सौंप दिया था। प्रबंधन समिति ने रिक्ति को अधिसूचित नहीं किया। उसी समय, दो प्रतिस्पर्धी दावेदारों के बीच प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए विवाद उत्पन्न हुआ था। यहां ऐसा नहीं है।

31. यह प्रस्तुत करना कि इंटरमीडिएट अधिनियम के प्रावधान, जिस हद तक वे बोर्ड अधिनियम के लिए असंगत थे, इसलिए, बल खो देते हैं, आकर्षक है क्योंकि उन विनियमों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए एक अलग विधि प्रदान की थी।

32. सबसे पहले, वह सिद्धांत इस अंतर-न्यायालय अपील के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है क्योंकि विवाद बोर्ड अधिनियम के संदर्भ में नहीं, बल्कि आयोग अधिनियम के प्रवर्तन को देखते हुए उत्पन्न हुआ है। इस अधिनियम में राज्य सरकार के सहायता अनुदान के अंतर्गत इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद पर मूलभूत रिक्तियों के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। यह केवल रिक्तियों, मांगों और चयनों के निर्धारण के लिए प्रदान करता है। इसमें आयोग अधिनियम की धारा 10 इस प्रकार है:-

“10. रिक्तियों का निर्धारण, मांग और चयन प्रक्रिया.-(1) सीधी भर्ती द्वारा शिक्षक या प्रशिक्षक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधन या प्राधिकृत अधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान मौजूदा या रिक्त होने की संभावना वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और, संस्था के प्रमुख के पद के अलावा किसी अन्य पद के प्रकरण में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4) और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करना, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 2020) और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देश, और रिक्तियों को आयोग को इस तरह से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है, जो निर्धारित किया जा सकता है। आयोग पात्रता का निर्णय करेगा और तदनुसार प्राप्त रिक्तियों को निर्धारित तरीके से विज्ञापित करेगा।

(2) शिक्षकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए धामक और भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्ति के संबंध में, उस धर्म विशेष के शिक्षाविदों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करके चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी? ”

33. उक्त प्रावधान का एक संक्षिप्त अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल ऐसी रिक्तियों के खिलाफ चयन के लिए की जाने वाली मांगों के लिए मूल रिक्तियों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए और चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मौजूद है। नियम 28 के साथ पढ़ें, रिक्तियों के निर्धारण और अधिसूचना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तैयार संदर्भ के लिए यह नीचे लिखा है: -

“28. रिक्तियों का निर्धारण और अधिसूचना। (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधन या प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) या निदेशक (बुनियादी शिक्षा) या निदेशक (प्रशिक्षण और रोजगार) या अटल आवासीय विद्यालयों के महानिदेशक के माध्यम से रिक्तियों को अधिसूचित करेगा। जैसा भी प्रकरण हो, आयोग को इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से।

(2) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों का विवरण, जिसमें भर्ती के वर्ष के अंतिम दिन सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों सहित नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भर्ती के वर्ष के 15 जुलाई तक उप-नियम (1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा, और प्राधिकृत अधिकारी,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने कार्यालय के रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद, प्रत्येक श्रेणी के पद की रिक्तियों के संबंध में विषयवार और आरक्षित श्रेणी-वार रिक्तियों का समेकित विवरण तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण अधिकृत अधिकारी द्वारा भर्ती के उसी वर्ष के 31 जुलाई तक आयोग को भेजा जाएगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करना समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, भर्ती के किसी विशेष वर्ष के संबंध में आयोग को रिक्तियों की अधिसूचना के लिए अन्य तिथियां निर्धारित कर सकेगी।

(3) यदि उप-नियम (2) के अधीन रिक्तियों को अधिसूचित किए जाने के बाद, शिक्षक या अनुदेशक के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध या प्राधिकृत अधिकारी, इसके घटित होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उक्त उप-नियम के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा इसकी प्राप्ति के दस दिनों के भीतर इसे आयोग को भेजेगा।

(4) जहां भर्ती के किसी वर्ष के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधन या प्राधिकृत अधिकारी, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट तिथि तक रिक्तियों को अधिसूचित नहीं करता है या उक्त उप-नियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में विफल रहता है, वहां प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय में अभिलेख के आधार पर, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों का निर्धारण करेगा और उन्हें आयोग को अधिसूचित करेगा। उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट तरीके और तारीख तक।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के तहत आयोग को अधिसूचित रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसी संस्था के प्रबंधन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।

(5) अधिसूचित रिक्तियों के पद एक ही स्थानांतरण द्वारा नहीं भरे जाएंगे: बशर्ते कि विशेष परिस्थितियों में, यदि एक स्थानांतरण आवश्यक है, तो उक्त प्रक्रिया को यथाशीघ्र आयोग के ध्यान में लाना आवश्यक होगा, और एकल स्थानांतरण के परिणामस्वरूप रिक्त पदों को निदेशक द्वारा अधिसूचित पदों में शामिल माना जाएगा, और यह रिक्ति भी उसी चयन प्रक्रिया द्वारा कवर की जाएगी। चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी परिस्थिति में एक बार भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34. उक्त नियम के एक नंगे अवलोकन से, यह पता चलता है कि संस्था का प्रबंधन निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को आयोग अधिनियम की धारा 10 के अनुसार रिक्तियों की संख्या को सूचित करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, ऐसी रिक्तियों को भर्ती के वर्ष के 15 जुलाई तक अधिसूचित किया जाना है, जिसमें रिक्ति उत्पन्न होती है।

35. उप-नियम 4 के तहत, प्रबंधन की ओर से विफलता पर, प्राधिकृत अधिकारियों (जो इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रकरण में डी.आई.ओ.एस. होंगे) पर आगे का दायित्व डाला गया है कि वे अपने रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक संस्थान में रिक्तियों का निर्धारण करें और आयोग को सूचित करें। इसलिए, बोर्ड अधिनियम के तहत, आयोग अधिनियम के तहत, प्रबंधन समिति पर पहला दायित्व मौजूद है और विफल होने पर डीआईओएस मूल रिक्ति को अधिसूचित करने के लिए बाध्य है।

36. प्रकरण के वर्तमान सेट में, न तो व्यक्तिगत संस्थानों की प्रबंधन समिति और न ही डीआईओएस ने कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य किया है। व्यक्तिगत संस्थानों में (प्रधानाचार्य के पद पर) स्वीकार की गई थी, उसके खिलाफ न तो बोर्ड को अधिसूचित उन संस्थानों की प्रबंधन समिति (बोर्ड अधिनियम के तहत), या अधिकृत अधिकारी/डीआईओएस (आयोग अधिनियम के तहत) को ऐसी रिक्तियों, न ही बोर्ड या डीआईओएस ने प्रासंगिक समय पर ऐसी रिक्तियों को निर्धारित करने और अधिसूचित करने के लिए कार्य किया है। इस प्रकार, सभी मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण को मूल रिक्तियों के खिलाफ काम करने के लिए वर्णित किया गया है, जो प्रासंगिक समय पर अधिसूचित नहीं हैं।

37. आयोग अधिनियम के अधिभावी प्रभाव पर आते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसकी धारा 30 के तहत, उस अधिनियम को शिक्षकों और अनुदेशकों के चयन के संबंध में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधान पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रधानाचार्य (उक्त अधिनियम की धारा 2 (एन) के तहत) शामिल हैं। इसलिए, यह निवेदन कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और पूर्ववर्ती कानून (ऐसे संस्थानों में तदर्थ प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने) के प्रावधानों ने बल खो दिया है, हमारे द्वारा स्वीकृति के लिए बहुत व्यापक है।

38. जिस हद तक, आयोग अधिनियम विशेष रूप से तदर्थ प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रदान नहीं करता है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसलिए विधायिका ने तदर्थ



प्रधानाचार्यों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तदर्थ प्रधानाचार्यों के लिए प्रदान करने की आवश्यकता प्रबंधन की व्यक्तिगत समितियों की सनक और कल्पना पर या ऐसे संस्थान में वरिष्ठतम व्याख्याताओं की इच्छा पर नहीं उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, यह संदेह करने के लिए बहुत मौलिक है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान अपने प्रशासनिक प्रमुख के बिना कार्य नहीं कर सकता है या अस्तित्व में नहीं रह सकता है, जिसे इंटरमीडिएट कॉलेजों और हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के संबंध में प्रधानाचार्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके कार्यों और कर्तव्यों को इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। आमतौर पर, सेवाओं की शर्तें उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 जी के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं, जिन्हें उसके तहत बनाए गए विनियमों के साथ पढ़ा जाता है। वह संस्था के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं। उसके पास शिक्षण संकाय को छुट्टी मंजूर करने और उनके कर्तव्यों को सौंपने और संस्थान की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की निगरानी करने की शक्ति है। बोर्ड परीक्षाओं सहित परीक्षा के संचालन के संबंध में, वह अन्य दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करने के अलावा, किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज के कामकाज को सुनिश्चित करने के अलावा, वैधानिक प्राधिकरण के रूप में संस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

39. इसलिए, यह सत्य के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक इंटरमीडिएट कॉलेज अपने प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति के बिना या किसी व्यक्ति को एक तदर्थ क्षमता में, एक विधिवत नियुक्त प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, एक तदर्थ क्षमता में प्रधानाचार्य के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किए बिना अस्तित्व में हो सकता है। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमन के अध्याय 1, खंड 9, 10, 11 और 12 में निम्नानुसार है: -

“9. प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्य— प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य, अपने पद से संबंधित समस्त कर्तव्यों के अतिरिक्त वे सभी दायित्व निभाएंगे जो उनके पद से संबंधित हैं, तथा उन कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए वे प्रबंध समिति के प्रति, संस्था के प्रबंधक के माध्यम से, उत्तरदायी होंगे। इन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।



10. प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और उनके पास अपनी संस्था के आंतरिक प्रबंधन और अनुशासन के लिए आवश्यक शक्तियां होंगी, जिनमें शामिल हैं:

(i) छात्रों के दाखिले और वापसी और निष्कासन अथवा निष्कासन की सिफारिश सहित उनकी सजा; पुस्तकालय, वाचनालय और पुरस्कार के लिए पाठ्य पुस्तकों, पुस्तकों और पत्रिकाओं का चयन; समय-सारणी की व्यवस्था और विद्यालय समय-सारणी से संबंधित स्टाफ के सदस्यों के कर्तव्यों का आवंटन; परीक्षा और परीक्षण आयोजित करना; छात्रों को पदोन्नति और, हिरासत, सभी फोर्निंस और स्कूलों के रजिस्ट्रारों और छात्रों की प्रगति रिपोर्ट का रखरखाव और उन्हें अपने अभिभावकों को भेजना; विद्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर, उपकरण और उपकरण और उनकी मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए मांग की तैयारी; खेलों और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का संगठन; छात्रों के स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार के लिए प्रावधान करना; विद्यालय परिसर के अंदर या बाहर शैक्षिक उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना; नियुक्ति, पदोन्नति, नियंत्रण और दंड जिसमें अवर सेवकों को हटाना और बर्खास्तगी शामिल है, इसके अधीक्षक के माध्यम से छात्रावास का नियंत्रण।

(ii) शिक्षकों, लिपिकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और अवर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं और कैरेक्टर रोल का रखरखाव; अपने चरित्र रोल में प्रविष्टियां करना और संबंधित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में बताना; क्लर्कों और पुस्तकालयाध्यक्षों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण; उनका निलंबन, और उनकी पुष्टि, पदोन्नति और दक्षता सीमा को पार करने के लिए सिफारिशें करना, संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करना; शिक्षकों, क्लर्क और पुस्तकालयाध्यक्षों के खिलाफ प्रबंधन समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना; (ख) अकादमिक परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए समिति को उनके आवेदनों की सिफारिश करना, शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति देना।

(iii) सभी बालक निधियों का नियंत्रण और प्रशासन; यह प्रधानाचार्य का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसी प्रत्येक निधि केवल उस वस्तु के लिए खर्च की जाए जिसके लिए इसकी अनुमति है; और यदि किसी वस्तु पर बचत होती है, तो उस निधि के लिए



वसूल किए गए शुल्क का ठहराव; प्रबंधन द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर फ्रीशिप और आधा-फ्रीशिप प्रदान करना; वजीफा और छात्रवृत्ति राशि का आहरण और वितरण।

11. वित्तीय और अन्य प्रकरण में जिनके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य प्रबंधक के माध्यम से उसे जारी किए गए प्रबंधन समिति के निर्देशों का पालन करेंगे।

12. प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य संस्था के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच पत्राचार का माध्यम होगा।”

40. इसलिए, कानून में यह मान्यता नहीं दी जा सकती है कि एक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक तदर्थ प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान के अभाव में, विधायी इरादा सभी परिस्थितियों में कोई तदर्थ/कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रदान नहीं करने के लिए व्यक्त किया गया है। वास्तव में, आयोग अधिनियम के प्रावधान इस आशय के लिए चुप हैं, लेकिन इंटरमीडिएट अधिनियम के लिए असंगत नहीं हैं। जबकि वे नियमित नियुक्तियों का प्रावधान करते हैं, विधायिका ने अपने विवेक से तदर्थ/कार्यवाहक व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया है, जैसा कि बोर्ड अधिनियम के तहत किया गया था। हालांकि, इस संबंध में कानून की व्याख्या करते समय कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है क्योंकि बोर्ड अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, एक समान स्थिति मौजूद थी। किसी भी विपरीत प्रावधान के अभाव में, विनियमन के प्रावधानों की व्याख्या की गई और यह प्रदान करने के लिए पढ़ा गया कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए आनुपातिक वेतन भुगतान भी उत्पन्न हो सकता है।

41. उस हद तक, आयोग अधिनियम चुप है, यह राज्य सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत इंटरमीडिएट कॉलेज में तदर्थ/कार्यवाहक प्राचार्य पर नियुक्ति के प्रावधानों को नकारता नहीं है। हम शिक्षकों के चयन के संबंध में शब्दों को पढ़ने के इच्छुक हैं? आयोग अधिनियम की धारा 30 में प्रतिबंधात्मक रूप से दिखाई देने के लिए - केवल ऐसे शिक्षकों के नियमित चयन का संकेत देना और संदर्भित करना। उस सीमा तक, आयोग अधिनियम के प्रावधान इंटरमीडिएट अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे। नतीजतन, उस सीमा तक, एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति, एक नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बाद, इस तरह के मूल पद पर जारी रखने के अधिकार के बाद कभी भी दावा नहीं कर सकता है। यह प्रावधान केवल आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाले अंतराल के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपबंध कर सकता है न कि ऐसी संस्था की प्रबंधन समिति की इच्छा के लिए। इसलिए, की गई व्यवस्था आयोग अधिनियम की धारा 30 के कठोर परिणामों से सुरक्षित रह सकती है। उपरोक्त कारण से, उस अधिनियम की धारा 31(3) भी मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण द्वारा दावा किए गए अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती है।

42. स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य की निरंतरता किसी भी अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति में उस अवधि के लिए उच्च वेतन प्राप्त करने के अधिकार के अलावा कोई अधिकार पैदा नहीं कर सकती है, जिसके लिए वह प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर सकता है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि **धनेश्वर सिंह चौहान (पूर्वोक्त)** में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत की पुष्टि के रूप में **नरबदेश्वर मिश्रा (पूर्वोक्त)** में लगातार लागू किया गया है (ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में), 40 से अधिक वर्षों के लिए, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पुनः पुष्टि की आवश्यकता है क्योंकि यह सिद्धांत समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है, समानता में। यह स्वीकार करने के बाद कि एक व्यक्ति को कानून में मौजूद आवश्यकता के माध्यम से एक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना आवश्यक है और उसे ऐसे संस्थान में किसी भी अन्य शिक्षक की तुलना में उच्च और अधिक कठिन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, ऐसे कर्तव्यों के अनुरूप उच्च वेतन प्राप्त करने का उसका अधिकार कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है।

43. उस न्यायसंगत अधिकार को हराने के लिए कोई नकारात्मक परिस्थिति मौजूद नहीं दिखाई गई है। वास्तव में, यह लंबी अवधि के लिए पुष्टि पा सकता है जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों ने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है।

44. राज्य द्वारा उठाई गई आगे की आपत्ति कि मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति प्रबंधन समिति द्वारा बोर्ड या अधिकृत अधिकारी/डीआईओएस को की गई किसी भी अधिसूचना के अभाव में अमान्य थी, यह भी हमें प्रभावित नहीं करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, हालांकि इस कार्य की शुरुआत (कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए) प्रबंधन समिति के हाथों में उत्पन्न होता है- जिसे रिक्ति के होते ही अधिसूचित करना चाहिए, साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों के सभी सेवा रिकार्ड उपलब्ध हैं और डीआईओ सहित सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से बनाए रखा जाता है। एस., जिसका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। इसलिए, मूल रिक्तियों की घटना



प्रबंधन समिति या बोर्ड या डीआईओएस के लिए एक अप्रत्याशित घटना नहीं है। त्यागपत्र, मृत्यु आदि के प्रकरण को छोड़कर, अन्य सभी रिक्तियों के बारे में पहले से सभी को पता है। किसी भी प्रकरण में, बोर्ड अधिनियम के तहत, और अब आयोग अधिनियम में, यह सांविधिक कानून की योजना नहीं है कि जब तक प्रबंधन समिति रिक्तियों को अधिसूचित नहीं करती है, तब तक इंटरमीडिएट कॉलेज में कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है या अधिसूचित नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत, विधायी जनादेश बना रहता है, यदि प्रबंधन समिति प्रश्न में भर्ती वर्ष (आयोग अधिनियम के तहत) के 15 जुलाई तक ऐसी रिक्ति को अधिसूचित करने में विफल रहती है, तो डीआईओएस/अधिकृत अधिकारी, ऐसी रिक्ति को अधिसूचित करने के लिए बाध्य है।

45. इसके अलावा, डीआईओएस के साथ इस तरह की रिक्ति के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण इनमें से प्रत्येक प्रकरण में मौजूद है, क्योंकि मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण के हस्ताक्षर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, इससे पहले कि उन्हें अपने संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। एक बार जब वह कार्रवाई की गई और संबंधित कर्तव्यों को बिना किसी आपत्ति के निर्वहन किया गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिक्तियों के अस्तित्व के बारे में डीआईओएस/प्राधिकृत अधिकारी सहित सांविधिक अधिकारियों को पता था।

46. इसलिए, ऐसी रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए प्रबंधन समिति की ओर से विफलता को मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण के उच्च वेतन का भुगतान करने के अधिकार को हराने के लिए अलग-थलग नहीं देखा जा सकता है। समान रूप से, डी.आई.ओ.एस./अधिकृत अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। रिक्तियों को अधिसूचित करने से पहले लंबा समय बीत चुका है। फिर भी प्रत्यर्थी राज्य को यह स्वीकार किया जाता है कि अभी तक कोई नई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है- जैसा कि किसी भी याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को अपने संबंधित इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका में किया गया दावा कानून और इक्विटी में भी अच्छी तरह से स्थापित था।

47. जिस हद तक विद्वान एकल न्यायाधीश ने आयोग अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है, जो याचिकाकर्तागण के अधिकारों को पराजित करता है, यह हमारे द्वारा पेश किए गए



प्रावधान से भिन्न रह सकता है। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को सिद्धांत रूप में अपास्त किया जाता है।

48. जहां तक राहत पहुंचाई जानी है-

(i) पहले यह घोषित किया जाता है कि मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता अपने संबंधित इंटरमीडिएट कॉलेजों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में तब तक बने रहने के हकदार होंगे, जब तक कि ऐसी संस्थाओं को कोई नियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(ii) कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में उनके बने रहने की अवधि के लिए, मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता बिना किसी अन्य या आगे की राहत के मूलधन के उच्च वेतन के भुगतान के हकदार होंगे।

(iii) उस अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वेतन का अधिक भुगतान किया जाना है, मूल याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में अपने हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से ऐसा अधिक वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे। उस राशि की गणना की जा सकती है और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर मूल याचिकाकर्तागण/अपीलकर्तागण को भुगतान किया जा सकता है।

49. विशेष अपील स्वीकृत किया जाता है। लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

25 मार्च, 2026

भानु